

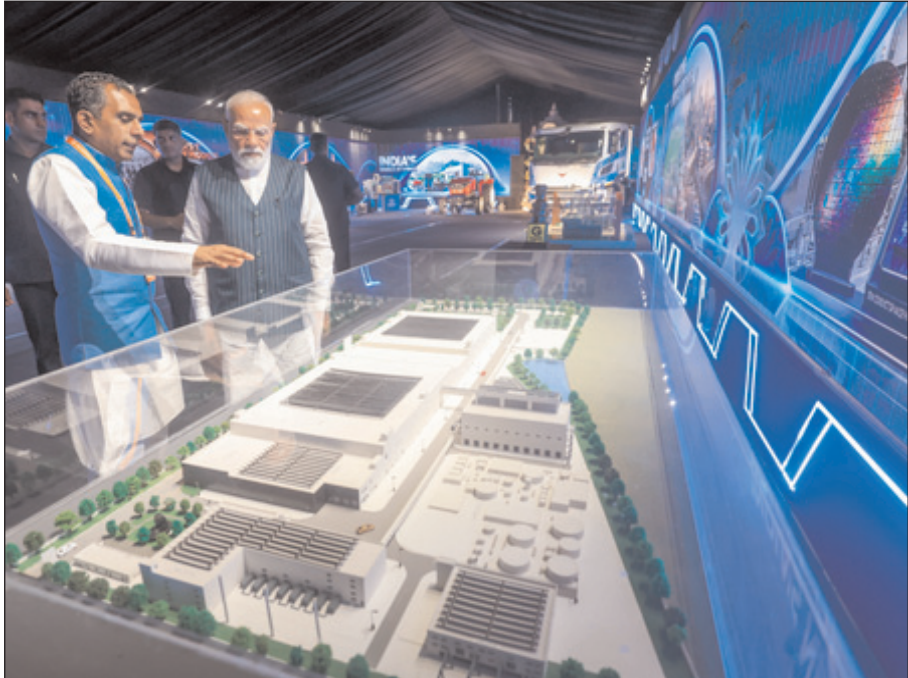
चिप डिजाइन से लेकर स्वदेशी एआई मॉडल तक, भारत बना रहा मजबूत तकनीकी इकोसिस्टम: सरकार

एजेंसी ■ नई दिल्ली

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर तकनीक के तेजी से विकसित होते दौर में भारत अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, देश सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के हर महत्वपूर्ण हिस्से में क्षमता विकसित कर रहा है, जिसमें चिप डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, एडवांस्ड पैकेजिंग, उपकरण निर्माण और कच्ची सामग्री शामिल हैं। अब तक भारत में विभिन्न तकनीकी नोड्स पर सात चिप्स का सफल निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 12 नैनोमीटर जैसे उन्नत नोड्स भी शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, भारत ने छह राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें कुल निवेश प्रतिबद्धता 1.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं में सिलिकॉन और क्वांटम सेमीकंडक्टर फैब, डिस्प्ले निर्माण इकाइयां और एडवांस्ड पैकेजिंग सुविधाएं शामिल हैं। इनमें से तीन इकाइयों ने व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है, जो इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक विनिर्माण की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है।

फैक्टशीट के मुताबिक, अप्रैल



2026 तक देश की 75 संस्थाओं द्वारा 211 चिप्स का टेप-आउट किया जा चुका है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती घरेलू डिजाइन क्षमता को दर्शाती है और बताती है कि देश अब वैश्विक चिप डिजाइन परिदृश्य में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। सरकार ने जुलाई 2026 में 'सेमिकॉन 2.0' कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस

कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर बौद्धिक संपदा (आईपी), चिप डिजाइन और सिस्टम डिजाइन को प्रोत्साहन देना है। सरकार का मानना है कि इससे भारत एक वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन हब के रूप में और मजबूत होगा।

सरकारी बयान में कहा गया है कि सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की रीढ़ हैं। स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, उपग्रह, रक्षा प्रणालियां और एआई-आधारित

तकनीकों सभी उन्नत चिप्स पर निर्भर हैं। वहाँ एआई के विस्तार के साथ हाई-परफॉर्मंस कंप्यूटिंग, विशेष प्रोसेसर और उन्नत चिप्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी कारण सेमीकंडक्टर और एआई तकनीकों एक-दूसरे से गहराई से जुड़ती जा रही हैं।

इस बदलते तकनीकी परिदृश्य को देखते हुए भारत केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि कंप्यूटिंग

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने पर भी जोर दे रहा है। इसी दिशा में सरकार की इंडियाएआई मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

करीब 10,372 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इंडियाएआई मिशन ने पिछले एक वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। जून 2026 तक इस मिशन के तहत उपलब्ध साझा कंप्यूटिंग क्षमता बढ़कर 45,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) तक पहुंच गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 तक 237 परियोजनाओं ने सब्सिडी वाली एआई कंप्यूटिंग सुविधा का उपयोग किया है। इन परियोजनाओं को कुल 93.18 लाख जीपीयू घंटे उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे देश के शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं को एआई मॉडल विकसित करने, उन्हें प्रशिक्षित करने, परीक्षण करने और अनुसंधान गतिविधियां संचालित करने के लिए अपेक्षाकृत कम लागत पर उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग शक्ति प्राप्त हो रही है।

सरकार का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य भारतीय नवाचारकर्ताओं के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करना और देश में एआई अनुसंधान एवं विकास को गति देना है।

स्वतंत्रता दिवस पर 1,057 कर्मियों को सम्मान, 301 को गैलेंट्री मेडल

एजेंसी ■ नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर केंद्र सरकार ने पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस और जेल सेवाओं के 1,057 कर्मियों को गैलेंट्री और सर्विस मेडल देने का ऐलान किया है।

इनमें 301 गैलेंट्री मेडल, 92 प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस और 664 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शामिल हैं।

इसके अलावा CBI के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है।

301 कर्मियों को गैलेंट्री मेडल कुल 301 गैलेंट्री मेडल में 272 पुलिसकर्मी और 29 फायर सर्विस कर्मी शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 197 कर्मी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के 51, नॉर्थ-ईस्ट के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मियों को भी गैलेंट्री मेडल दिया गया है। यह सम्मान ऐसे कर्मियों को दिया जाता है, जिन्होंने जान बचाने, संपत्ति की रक्षा करने, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाई।

92 कर्मियों को प्रेसिडेंट्स मेडल सरकार ने 92 कर्मियों को प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड



सर्विस देने का ऐलान किया है। इनमें 83 पुलिस सेवा, 4 फायर सर्विस, 3 सिविल डिफेंस एवं होम गार्ड और 2 करेक्शनल सर्विस के कर्मी शामिल हैं। यह सम्मान सेवा में विशेष और उत्कृष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है।

664 कर्मियों को मेरिटोरियस सर्विस मेडल इसके अलावा 664 कर्मियों को मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस (MSM) दिया गया है। इनमें 606 पुलिस, 28 फायर सर्विस, 18 सिविल डिफेंस एवं होम गार्ड और 12 करेक्शनल सर्विस के कर्मी शामिल हैं। यह मेडल कर्तव्य के प्रति समर्पण और बेहतर सेवा के लिए दिया जाता है।

CBI के 21 अफसर-कर्मियों को भी राष्ट्रपति पदक CBI के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राष्ट्रपति पदक

से सम्मानित किया गया है। इनमें 6 को PSM और 15 को स्क्रू दिया गया है। PSM पाने वालों में शोभा दत्ता, मनोज बनर्जी, गिन्नी राणा, संजय कुमार समाल, रमेश चंद और मदन लाल धीमान शामिल हैं। इनमें SP, ASP, DSP और ASI स्तर के अधिकारी-कर्मचारी हैं। स्क्रू पाने वालों में छक्का इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल के साथ लीगल और टेक्निकल स्टाफ भी शामिल हैं। ये CBI की दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, पटना, चंडीगढ़, मद्रास और बेंगलुरु समेत अलग-अलग यूनिट में तैनात हैं। इन पुरस्कारों के जरिए CBI के जांच, कानूनी, तकनीकी, प्रशासनिक और फोल्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मियों के योगदान को सम्मानित किया गया

राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले को किया रद्द

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही को रद्द किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नाग को बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस मामले में राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने के लिए कानून के तहत जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। प्रक्रिया में इस कमी पर ध्यान देते हुए शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और जारी किए गए समन को रद्द कर दिया।

यह मामला 2022 में 'भारत जोड़ी यात्रा' के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। इसमें उन्होंने वीर सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' बताया था। साथ ही, कांग्रेस सांसद ने कहा था कि सावरकर 'अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।' वकील नृपेंद्र पांडे ने इसको लेकर निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने राहुल गांधी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत आरोप लगाए थे।



नृपेंद्र पांडे का दावा था कि ये टिप्पणियां समाज में नफरत फैलाने के इरादे से की गई थीं। पांडे को शिकायत में यह भी कहा गया था कि महात्मा गांधी ने पहले सावरकर को देशभक्त माना था। जून 2023 में, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पांडे की शिकायत खारिज कर दी, जिसके बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने सेशंस कोर्ट में इसे चुनौती दी।

सेशंस कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और मामले को वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया। इसके बाद, दिसंबर 2024 में निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पहली नजर में आईपीसी 153(ए) और 505 के तहत केस मानते हुए उन्हें समन जारी किया था। इसी मामले में 4 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

15 महीनों से अमेरिकी बॉर्डर पर कोई रिहाई नहीं: ट्रंप प्रशासन

एजेंसी ■ वॉशिंगटन

सीमा पर सख्त सुरक्षा उपायों और सीमा पार करने की घटनाओं में आई ऐतिहासिक गिरावट की वजह से अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर अवैध रूप से प्रवेश करने वाले प्रवासियों को रिहा किए जाने का सिलसिला लगातार 15वें महीने भी शून्य रहा। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्वोरिटी (डीएचएस) और अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने बताया कि जुलाई में बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों ने दक्षिण-पश्चिम सीमा पर 9,295 लोगों को पकड़ा। यह संख्या जून की तुलना में 6 प्रतिशत कम थी।

एजेंसियों ने बताया कि पूरे देश में बॉर्डर पेट्रोल द्वारा पकड़े गए लोगों की संख्या पिछले महीने की तुलना में 1 प्रतिशत घटकर 11,298 हो गई। डीएचएस सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने कहा, 'इस महीने भी नतीजे साफ हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का बॉर्डर सिक्वोरिटी एजेंडा व्यवस्था बहाल कर रहा है और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।

उन्होंने कहा, 'डीएचएस हमारे इमिग्रेशन कानूनों को लागू करने, सीमा को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि जो लोग हमारे देश में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं, उन्हें तुरंत वापस भेजा जाए।

ट्रंप प्रशासन ने बताया कि



जुलाई में दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर पकड़े गए लोगों की संख्या बाइडेन प्रशासन के दौरान दर्ज किए गए मासिक औसत से 94 प्रतिशत कम थी। यह संख्या दिसंबर 2023 के सबसे ज्यादा स्तर से 96 प्रतिशत कम थी और जुलाई 2024 के छह दिनों में दर्ज की गई संख्या से भी कम थी। जारी बयान के अनुसार, मौजूदा वित्त वर्ष में जुलाई तक दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 1992 से 2024 के वित्त वर्षों के दौरान किसी एक महीने के औसत से भी कम थी। अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) कमिशनर रॉडनी एस. स्कॉट ने कहा, 'साफ नीति, सख्त कार्रवाई और समर्पित फ्रंटलाइन कर्मचारी हमारी सीमाओं पर अच्छे नतीजे दे रहे हैं।

स्कॉट ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप और सेक्रेटरी मुलिन के सहयोग से सीबीपी हमारे देश को अवैध रूप से सीमा पार करने वालों, खतरनाक लोगों और गैर-कानूनी ड्रास से सुरक्षित रख रहा है, साथ ही वैध व्यापार और यात्रा को भी जारी रखे हुए है।

मान. विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन

मान. राजेश भगवान

पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस

मंत्री छ.ग. शासन

स्वतंत्रता दिवस की 80 वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश व देशवासियों को दैनिक विश्व केसरी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 को अवकाश होने के कारण अगला अंक 17 अगस्त 2026 को प्रकाशित होगा

पीएम मोदी ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय की भूमिका की सराहना की, बोले-हर क्षेत्र में बनाई पहचान

एजेंसी ■ वाशिंगटन

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग-अलग क्षेत्रों में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की उपलब्धियों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ इसका लगातार जुड़ाव देश के लिए ताकत का जरिया बना हुआ है। नेशनल अलायंस ऑफ इंडियन ऑर्गनाइजेशन (एनएआईओ) को भेजे गए एक संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस और अमेरिका की 250वीं सालगिरह का जश्न दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच करीबी संबंध को दिखाता है। पीएम मोदी ने 13 अगस्त के भेजे गए संदेश में कहा, 'यह जानकर खुशी हो रही है



कि नेशनल अलायंस ऑफ इंडियन ऑर्गनाइजेशन (एनएआईओ) भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस और संयुक्त राज्य अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है।

पीएम मोदी ने कहा कि साथ मिलकर मनाया जा रहा है जश्न उन मूल्यों को दिखाता है, जो नई दिल्ली और वाशिंगटन को जोड़ते हैं।

उन्होंने कहा, 'ये जश्न भारत और अमेरिका के बीच करीबी संबंधों को दिखाते हैं, जो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा, 'मां भारती और प्रवासी भारतीयों के बीच मजबूत संबंध ऐसी कोशिशों में भी दिखता है, जो हमेशा हमारे देश के लिए ताकत का जरिया रहा है।

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था में चार नए सदस्यों को दिलाई पद की शपथ

विश्व केसरी■
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुरेंद्र पंढरीनाथ तवाडे ने महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के न्यायिक सदस्य के तौर पर शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने शुक्रवार को मुंबई के लोक भवन में आयोजित एक संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस तवाडे को पद की शपथ दिलाई।

रिटायर्ड चीफ डिस्ट्रिक्ट जज सुवर्णा किशोर केओले ने भी महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के न्यायिक सदस्य के तौर पर शपथ ली। रिटायर्ड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश गुप्ता और महाराष्ट्र की रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला ने भी महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्था के गैर-न्यायिक सदस्यों के तौर पर शपथ ली। ये नियुक्तियां गवर्नर ने नए लोकायुक्त एक्ट 2023 के तहत कीं। सभी सदस्यों को नियुक्ति 5 साल के कार्यकाल के लिए या 70 साल की उम्र पूरी होने तक (जो भी पहले हो) की गई है।

इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, लोकायुक्त जस्टिस विद्यासागर कनाडे (रिटायर्ड), चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और सरकार के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। गवर्नर के सेक्रेटरी डॉ. प्रशांत नारनवरे ने लोकायुक्त संस्था के चार सदस्यों को नियुक्ति के वारंट पढ़कर सुनाए। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राष्ट्र गीत, राष्ट्रगान और महाराष्ट्र गीत के गायन से हुई और समापन राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इसके पहले 14 जुलाई को महाराष्ट्र के लोकायुक्त जस्टिस वी.एम. कनाडे (सेवानिवृत्त) ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात कर वर्ष 2025 के लिए लोकायुक्त



और उप-लोकायुक्त के कामकाज की 53वीं संयुक्त वार्षिक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में वर्ष 2025 के दौरान कार्यालय में प्राप्त शिकायतों, उनके निपटारे और संस्था के कामकाज का विवरण दिया गया है।

लोकायुक्त कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में कुल 8,547 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 3,869 शिकायतों को पंजीकृत नहीं किया गया, क्योंकि वे अन्य अधिकारियों को भेजे गए आवेदनों की प्रतियां थीं या उन पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। इसके बाद कुल 4,678 शिकायतों को विधिवत दर्ज किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 की शुरुआत में पिछले वर्षों के 4,287 मामले पहले से लंबित थे। इस तरह पूरे वर्ष के दौरान लोकायुक्त कार्यालय के पास सुनवाई और निपटारे के लिए कुल 8,965 मामले थे। इनमें से 4,885 मामलों का निपटारा कर दिया गया, जबकि वर्ष के अंत तक 4,080 मामले लंबित रहे।

महाराष्ट्र में शुरू होगी महा-आईडी व्यवस्था, घर बैठे मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

विश्व केसरी■
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार अब राज्य के हर नागरिक को एक डिजिटल पहचान देगी। इसके लिए सरकार 'महा-आईडी' जारी करेगी। इसका मकसद सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से तेज, पारदर्शी और घर बैठे सरकारी सेवाएं देना है। यह कोई अलग पहचान पत्र नहीं होगा। 'महा-आईडी' सीधे व्यक्ति के आधार कार्ड से जुड़ी एकीकृत पहचान संख्या होगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे एआई और आईटी समाधान अपनाएं, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं सीधे घर से मिल सकें। इसी डिजिटल गवर्नेंस पहल का अहम हिस्सा 'महा-आईडी' होगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 'इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग के अंतर्गत 'महा-सारथी' पोर्टल के जरिए चलाया जाएगा। नागरिक तय पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे और जरूरी जानकारी देंगे। आधार फ्रेमवर्क को शामिल करते हुए डिजिटल महा-आईडी तैयार की जाएगी। नागरिक इसी एक आईडी से विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।

'महा-आईडी' देने के बाद नागरिकों को योजनाओं, जानकारी, सब्सिडी और सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिर्फ 'महा-आईडी' बतानी होगी। सरकार के पास पहले से ही डेमोग्राफिक सर्वेक्षण, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे अहम रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसलिए हर आवेदन के साथ नागरिकों को भौतिक दस्तावेज बार-बार जमा नहीं करने होंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस पहल की रूपरेखा पेश कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद आधिकारिक



परियोजना लॉन्च होगी। यह एकीकृत प्रणाली छात्रों, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, महिला उद्यमियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधे लाभ देगी। अभी छात्रों को राज्य छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा पोर्टलों पर अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। किसानों को सब्सिडी के लिए बार-बार पहचान, जमीन और बैंक का ब्योरा देना होता है। इसी तरह सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को भी ऐसे प्रमाण पत्र दोबारा जमा करने पड़ते हैं जो पहले से अन्य विभागों के रिकॉर्ड में होते हैं।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि पहले से सत्यापित डेटा अब पात्र सेवाओं में अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा। इससे अनावश्यक दस्तावेज जमा करने से छुटकारा मिलेगा।

'महा-आईडी' और 'महा-सारथी' पोर्टल के एकीकरण से विभिन्न सरकारी विभाग और डिजिटल प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ जाएंगे। इससे एक अत्यधिक इंटरऑपरेबल डिजिटल गवर्नेंस नेटवर्क बनेगा। जब राज्य के विभाग अपना डेटा सिंक्रोनाइज करेंगे।

करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक हटाई

विश्व केसरी■
नई दिल्ली। करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर लगी रोक हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। राज्य सरकार ने मद्रु

चुनौती क्यों बेंच ने सवाल किया, 'राज्य द्वारा त्रासदी के पीड़ितों को रोजगार देने में दिक्कत क्या है तमिलनाडु सरकार को तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी पेश हुए। मद्रास हाईकोर्ट की मद्रु बेंच ने सितंबर 2025 में करूर में हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था हाईकोर्ट का कहना था कि इस तरह की नियुक्तियां असंवैधानिक

अदालत ने कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को तुरंत आर्थिक राहत देना है। इसे किसी सार्वजनिक त्रासदी के बाद आम पुनर्वासि उपाय के तौर पर नहीं बढ़ाया जा सकता। यह भगदड़ सितंबर 2025 में करूर में टीवीके नेता विजय की रैली के दौरान हुई थी। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 8 बच्चे शामिल थे। इसके अलावा 46 लोग घायल हुए थे।



बेंच के 27 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा,

'राज्य ने एक दुखद त्रासदी के बाद पीड़ित परिवारों को रोजगार देने की पेशकश की थी। इसके खिलाफ

वहाब आलम नेपाल के पांच ऑपरेटरों के जरिए आईएसआई हैंडलर्स से संपर्क में था, जांच में बड़ा खुलासा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम की गिरफ्तारी के बाद स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) लगातार जांच में जुटी है। इस दौरान एसटीएफ को वहाब आलम के नेपाल में मौजूद पांच साथियों के नाम पता चले हैं। एसटीएफ के अधिकारियों ने आलम के पास से मिले नेटबुक का डेटा डिकोड करके नेपाल में मौजूद इन पांच ऑपरेटर्स के नाम पता किए। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि एसटीएफ की लंबी पूछताछ के दौरान आलम टूट गया और उसने कबूल किया कि वह पाकिस्तान में अपने आईएसआई हैंडलर्स से संपर्क बनाए रखने के लिए नेपाल में मौजूद इन पांच ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे करता था।

ममता भागीरथी यादव सक्रिय सदस्य भाजपा

मौ बंजारी भाजपा मंडल बीरगांव पूर्व एल्डरमैन नगर निगम

भागीरथी यादव अध्यक्ष

मौ बंजारी भाजपा मंडल बीरगांव पूर्व एल्डरमैन नगर निगम

सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

विश्व केसरी■
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थ बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को क्यों नहीं दे रहे हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना एक जुर्म है और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए ऐसे कंटेंट की रिपोर्ट पुलिस को करना जरूरी है। अगर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी ऐसे मामलों की रिपोर्ट पुलिस को नहीं करते हैं तो वे क्रिमिनल तौर पर जवाबदेह बन जाते हैं। एक एनजीओ जस्ट राइट्स फॉर चाइल्ड की तरफ से दायर एक अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि केंद्र और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और पूछा कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की रिपोर्ट पुलिस को क्यों नहीं कर रहे हैं? सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का ने कहा, 'इन दिनों चल रहे इस मुद्दे को लेकर कि इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण के वीडियो न सिर्फ तेजी से फैल रहे हैं, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से बढ़ावा भी दिया जा रहा है। भारत सरकार ने इंस्टाग्राम को रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए हैं। हालांकि, 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सोशल मीडिया चलाने वाले सभी लोग - ये मध्यस्थ, चाहे वह मेटा हो, टेलीग्राम हो या कोई भी हो जो इन्हें चला रहा है - यह उनकी जिम्मेदारी है कि जब भी बच्चों के यौन शोषण का कोई वीडियो सामने आए, तो वे न सिर्फ उसे ब्लॉक करें बल्कि पुलिस को इसकी रिपोर्ट भी करें। एच.एस. फुल्का ने आगे कहा, 'सोशल मीडिया से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करने और देखने वालों के खिलाफ पोक्स एक्ट के तहत केस चलने की बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है।

15 अगस्त

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं!

आओ, मिलकर प्रतिज्ञा करें

न देश को झुकने देंगे, न तिरंगे को रूकने देंगे, हम एक हैं, हम नेक हैं, भारत माँ के सच्चे सपूत हैं।

पढ़ा हुआ मनुष्य ही स्वतंत्र है, क्योंकि ज्ञान ही असली आज़ादी का रास्ता है।

ज्ञान ही विकास है, शिक्षा ही सम्मान है, शिक्षित भारत समृद्ध भारत।

एक शिक्षित बच्चा, एक जागरूक परिवार, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है।

शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं।

शिक्षा से ही उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है।

शिक्षित बनें, संगठित रहें, संघर्ष करें।

डॉ. भीमराव अंबेडकर

जय हिन्द

जय भारत

वंदे मातरम्

पीहू शर्मा, प्राहिल शर्मा, आरुग शर्मा

15th of August Independence Day

सृष्टि पैरामेडिकल इस्टीट्यूट लाखे नगर रायपुर छग की ओर से प्रदेश व देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं



मान. श्री नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री



मान. श्री अमित शाह जी
केन्द्रीय गृहमंत्री



मान. श्री विष्णु देव साय जी
मुख्यमंत्री (छ.ग.)



मान. श्री टंकुराम वर्मा जी
कैबिनेट मंत्री (छ.ग.)



मान. श्री अरुण साव जी
उप मुख्यमंत्री (छ.ग.)



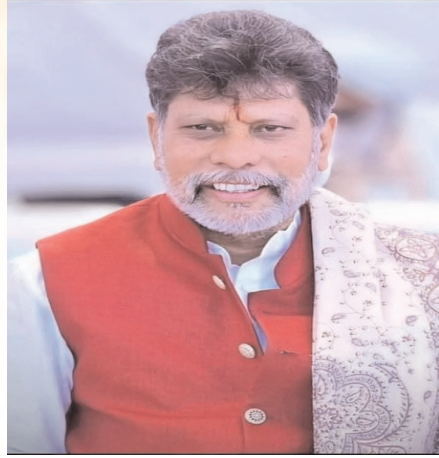
मान. श्री विजय शर्मा जी
उप मुख्यमंत्री (छ.ग.)



गौरीशंकर अग्रवाल
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छ.ग शासन



नंदकुमार साय



किरण देव
प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी (छ.ग.)



सनम जागड़े
अनुसूचित जाति आयोग



मोहम्मद ज. प. क. (सभापति)
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
जनपद पंचायत कसडोल
प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा
मोर्चा
प्रभारी रायपुर



श्रीमती गायत्री जाटवर
सरपंच



श्रीमती पूजा कमलवंशी
सरपंच



श्रीमती रंजनी राजेन्द्र
महिलांगे (सरपंच)



श्रीमती गीतांजली
मानिकपुरी (सरपंच)

आप सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

स्वतंत्रता वो नहीं
जो मिलती है,
स्वतंत्रता वो है
जिसे हम सहेजते हैं।
जय हिन्द!

— समस्त देशवासियों को —

15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस की
**हार्दिक
शुभकामनाएं!**

एक देश, एक संकल्प,
विकसित भारत का लक्ष्य।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग बलौदाबाजार

स्वतंत्रता संघर्ष के वीरों
के बलिदान से मिली है आज़ादी,
आओ मिलकर करें देश को
और भी समृद्ध और शक्तिशाली।

जय हिन्द! जय भारत!

15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस की
**हार्दिक
शुभकामनाएं!**

आइए, हम सब मिलकर देश की एकता,
अखंडता और प्रगति के लिए
संकल्पित हों।

**विकास खण्ड
शिक्षा अधिकारी कसडोल**
की ओर से
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

संकलनकर्ता :- प्रवीण ढोमने कसडोल

संपादकीय

बदलता भारत, बनता भारत

हम जिस भारत के रूप में उभरे हैं, और जिस भारत की हम अभी भी तलाश कर रहे हैं



डॉ. प्रियंका सौरभ

प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस हमें अपने राष्ट्र के अतीत पर चिंतन करने और भविष्य पर विचार करने का अवसर देता है। यह परिवर्तन केवल हमारी अर्थव्यवस्था, शहरों या प्रौद्योगिकी में ही नहीं, बल्कि आम भारतीयों की आकांक्षाओं, आत्मविश्वास और दृष्टिकोण में भी देखा गया है। आज का भारत 1947 में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए भारत से बहुत अलग है।

आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा अंतर यही है। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में संसाधनों की कमी थी, अवसर सीमित थे और विशाल जनसंख्या की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक चुनौती थी। भारत आज विश्व की महान आर्थिक शक्तियों में से एक है; आधुनिक उद्योग, विकसित होता बुनियादी ढांचा और उद्यमशीलता की नई भावना, महत्वाकांक्षी युवा पीढ़ी। सड़कों, हवाई अड्डों, मेट्रो, डिजिटल नेटवर्क और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण स्थान और लोग एक-दूसरे के करीब आ गए हैं। एक युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है, किसी दूसरे शहर की कंपनी में काम कर सकता है और यहां तक ? ?कि पूरे देश में लोगों को सेवा प्रदान करने वाला व्यवसाय भी चला सकता है। पिछली पीढ़ियों के लिए ऐसी संभावनाओं की कल्पना करना भी मुश्किल रहा होगा।

शायद इस बदलाव में प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा योगदान है। मोबाइल फोन अब सिर्फ संचार का साधन नहीं रह गया है। यह एक बैंक, कक्षा, बाजार, कार्यालय और सूचना का स्रोत बन गया है। ऑनलाइन भुगतान ने हमारे दैनिक जीवन में क्रांति ला दी है और अनेक सार्वजनिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। प्रौद्योगिकी ने भारत को सूचना और अवसरों के मामले में कई मायनों में अधिक जुड़ा हुआ और अधिक लोकतांत्रिक बनाया है। लेकिन प्रगति का सच्चा सूचक प्रौद्योगिकी नहीं है, बल्कि यह है कि प्रौद्योगिकी आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित करती है।

भारतीयों और उनके राष्ट्र के आत्मविश्वास में अद्भुत परिवर्तन आया है। कुछ पीढ़ियों के पहले, पश्चिम के प्रति प्रशंसा और कभी-कभी हीनता की भावना प्रचलित थी। आज, हमारे युवा खुद को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों के बराबर मानते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता, पेशेवर क्षेत्र, कला एवं खेल के क्षेत्र में भारतीय नागरिक विदेशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। साथ ही, भारत की संस्कृति, भाषाओं, परंपराओं और इतिहास का पुनरुद्धार हो रहा है। आधुनिकता और जड़ों से जुड़ाव की अवधारणा अब विरोधाभासी नहीं रह गई है।

प्रगति के बावजूद, हमारी समस्याएं कम नहीं हुई हैं। हमारे पास विश्व स्तरीय हवाई अड्डे और डिजिटल बुनियादी ढांचा है, लेकिन कुछ समुदाय अभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन व्यवसाय और कुशल कर्मचारी हैं, फिर भी लाखों युवा स्थिर और लाभकारी रोजगार की तलाश में हैं। शहरों के विकास के साथ-साथ, कई शहर प्रदूषण, भीड़भाड़ और खराब गहरी नियोजन से जूझ रहे हैं। आर्थिक विकास ने अपार अवसर पैदा किए हैं, लेकिन सभी नागरिकों को इसका समान लाभ नहीं मिल रहा है।

संतुलित आलोचना का महत्व यही पर है। अपने देश की कमियों से अवगत हुए बिना उससे प्रेम करना संभव नहीं है। वास्तव में, सच्ची देशभक्ति हमें उन चीजों को स्वीकार करने का साहस देती है जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। एक सशक्त लोकतंत्र में असहमति और आलोचना को सहन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय हित केवल आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति और अंतरराष्ट्रीय शक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें सामाजिक सद्भाव, सुदृढ़ संस्थाएं, समान अवसर, सभी नागरिकों के लिए गरिमा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास भी शामिल होना चाहिए। यदि देश का कोई भविष्य है, तो उसे कठिन प्रश्नों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास होना चाहिए।

हमारे लिए भी भारत की यह अवधारणा अनूठी है। भारत केवल आधुनिक युग की एक राजनीतिक इकाई नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास, विभिन्न परंपराओं, भाषाओं, दर्शनों और सांस्कृतिक प्रभावों से परिपूर्ण एक सभ्यता है। विविधता को स्वीकार करना और एकरूपता को सहेन इस सभ्यतागत स्वरूप को बनाए रखें और साथ ही तेजी से बदलती दुनिया की संभावनाओं को भी स्वीकार करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत प्रौद्योगिकियाँ और सांस्कृतिक जड़ों के बीच संतुलन होना चाहिए। आधुनिक शहर बनने चाहिए, लेकिन उनमें सामुदायिक भावना भी होनी चाहिए। हमें विश्व के साथ अधिक एकीकृत होने की आवश्यकता है, लेकिन अपनी संस्कृति को लेकर असुरक्षित नहीं होना चाहिए।

एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि उसने लोकतंत्र को कायम रखा और विकसित किया। अब तक, विभिन्न भाषाओं, धर्मों, भौगोलिक पृष्ठभूमि, समुदायों और आर्थिक स्थिति वाले लोगों से भरा यह विविध राष्ट्र संवैधानिक ढांचे के भीतर अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम रहा है। हालांकि यह लोकतंत्र अभी पूर्ण नहीं है, फिर भी असहमति एक ताकत हो सकती है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि लोग अभी भी अपने समाज के भविष्य पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे मतभेद विभाजन में न बदलें और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत की अवधारणा को कमजोर न करे।

कविता/देशगान



गोलेन्द्र पटेल

देश न केवल भू-धरा, जनमन का विश्वास।
संस्कृति, समता, चेतना, इसका दिव्य प्रकाश।

माटी, भाषा, लोक से, जिसका जुड़ा सनेह।
वही सच्चा देशप्रेम, निर्मल मन का नेह॥

प्रेम बने जब कर्ममय, जागे सत्य-विवेक।
देशभक्ति तब खिल उठे, सेवा-धर्म अनेक।

सीमा से संसद तलक, कर्तव्य रहे प्रधान।
श्रम, ईमान, विज्ञान से, बढ़ता देश-मान॥

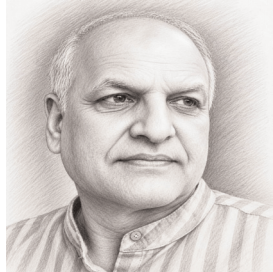
मातृभूमि की धूल में, जीवन का आधार।
जन्म-जन्म का जुड़ गया, इससे आत्म-संस्कार।

न्याय, समता, बंधुत्व से, सजता राष्ट्र-विहार।
संविधान की छाँह में, खिलता जन-संसार॥

द्रेष नहीं, सद्भाव हो, मानव हो पहचान।
अपना देश महान हो, हो जग का कल्याण।

प्रेम, त्याग, कर्तव्य से, रचें नया इतिहास।
वन्दे मातरम् गूँजता, भारत रहे प्रकाश॥

स्वतंत्रता दिवस यानी राष्ट्र निर्माण का संकल्प



गिरिश पंकज

भारत अपनी स्वतंत्रता के आठ दशकों की यात्रा पूर्ण कर रहा है। आठ दशक किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पड़ाव होते हैं, जहाँ पहुँचकर पीछे मुड़कर देखना और आगे का मार्ग प्रशस्त करना अनिवार्य हो जाता है। इन अस्सी वर्षों में निःसंदेह भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरिक्ष क्षेत्र में अभूतपूर्व 'भौतिक प्रगति' की है। आज हम दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं। लेकिन भौतिक विकास की इस चमचमाती इमारत के पीछे एक गहरी चिंताजनक सच्चाई भी छिपी है, हमारी सांस्कृतिक, नैतिक और राष्ट्रीय चेतना में आता क्षरण।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अस्सी वर्ष कम नहीं होते, लेकिन भौतिक उन्नति के बावजूद यदि देश विरोधी मानसिकता, सांस्कृतिक हीनता और कर्तव्यों से विमुखता बढ़े, तो यह चिंता का विषय है। आज का यश प्रश्न यही है कि क्या स्वतंत्रता केवल 'अधिकारों की अंधी दौड़' है या फिर यह 'नागरिक कर्तव्यों के गंभीर दायित्व' का दूसरा नाम है?

स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन की पराधीनता से मुक्ति या विदेशी शासकों के चले जाने का नाम नहीं थी। स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ था, अपने राष्ट्र, संस्कृति, परंपराओं और भविष्य का निर्माण स्वयं करने का अधिकार। परंतु समय के साथ, विशेषकर पिछले कुछ दशकों में, समाज में स्वतंत्रता की व्याख्या को बेहद संकुचित और स्थायी बना दिया गया है। ?हमने यही पढ़ा है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्य के अधिकार एक ऐसी स्वच्छंदता बन जाते हैं जो अंततः समाज और राष्ट्र को विनाश की ओर ले जाती है। ?जब हम केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो लोकतंत्र एक अराजक व्यवस्था में बदलने लगता है। आज देश में हर व्यक्ति को अपनी 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और 'अभिव्यक्ति की आजादी' की चिंता तो है, लेकिन उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जिस अनुशासन, नैतिक मूल्य और नागरिक कर्तव्य की आवश्यकता है, उससे लोग मुँह मोड़ रहे हैं।

यह कटु सत्य अत्यंत विचारणीय है कि पिछले डेढ़-दो दशकों में देश में एक ऐसी मानसिकता ने आकार लिया है जो अपने ही देश की गौरवशाली परंपराओं, सांस्कृतिक प्रतीकों और राष्ट्रीय अस्मिता पर आघात करती है। ?अपनी जड़ों से उखड़े हुए कुछ लोग आज आधुनिकता या प्रगतिशीलता के नाम पर भारत की सनातनी परंपराओं, ऋषि-मुनियों के चिंतन और धार्मिक प्रतीकों को नीचा दिखाने या गाली देने में गर्व महसूस करते हैं। यह वैचारिक खंडनी लेकिन सत्य बात कही है कि अगर अस्थील गालियां देना या दूसरों का भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही किसी का अधिकार बन गया है, तो उसका यह कर्तव्य भी है कि वह समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करे। स्वतंत्रता कभी भी

स्वतंत्रता दिवस स्वच्छंदता दिवस न बने



– साकार श्रीवास्तव 'फलक'

भारत यानी हम भारत वासियों को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। इसमें नयी बात क्या हुई? यह तो सर्व विदित तथ्य है। सच है, हमें स्वतंत्रता मिली ताकि हम स्व का तंत्र स्थापित करें व अपनी एक सुशासन व्यवस्था लागू करें। लेकिन अभी आजादी कहीं? हमें इंतजार था कि हमारा क्रांनु बने। चलिए, तंत्र की स्थापना हो गयी, अपना संविधान बन गया और और 26 जनवरी 1950 को 'हम भारत के नागरिक' के रूप में हमने इसे अंगीकार भी कर लिया कि अब हम अपने क्रायदे – क्रांनु मानेंगे। लेकिन व्यवहार में हुआ कुछ और ही। अब 'हम भारत के नागरिक' ने स्वाधीन होने का अर्थ अपनी मर्जी का मालिक होने से ले लिया। हमने स्वतंत्रता का अर्थ समझ लिया – यानी कुछ भी करो, कोई रोक-टोक नहीं। मतलब अब है—हर कोई 'राजा', और बाकी सब 'प्रजा'।

अपने वाहन चाहे वह दुपहिया हो या चौरपहिया सड़क पर या किसी के घर के आगे पाक करके देते हैं, आने जाने वालों को परेशानी से उनको कोई मतलब नहीं आखिर वे भी स्वतंत्र हैं।

सरकार में बाबुओं की लोकलुभावन सेलेरी और भौति – भौति के भत्तों के अलावा भी उनकी गौध दुष्टि 'बैंधी' पर रहती है। ऐसे पद पर पोस्टिड के लिए मोटी 'बैंधी' देने को तैयार रहते हैं। जहाँ मौका मिले झपट लो। महीने की पगार से कई गुना 'बैंधी'। कोई पूछे तो टका – सा जवाब, अरे साहब, हमें ऊपर मंत्री फक

नहीं देना है। हम स्वतंत्र जो हैं।

तत्परता से नहीं हुआ होगा, जितनी तेजी से देशभक्ति की बूस्टर डोज़ बाँटी जा रही है।

इस वैक्सीन की खासियत यह है कि यह बीमारी ठीक करे न करे, बीमारी का ध्यान जरूर भटका देती है।

बेरोजगारी का भूत चढ़ गया? देशभक्ति का झाड़ा लगावाइए।महंगाई डायन खाए जा रही है? देशभक्ति का ताबीज पहनिए।पानी नहीं आ रहा? भारत माता की जय बोलिए।घर में आटा गोला हो गया? देशभक्ति से अभिमंत्रित भूँक मारिए-शायद कंगाली का गोला आटा सुख जाए।

राजनीति ने आखिर हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति का महत्व समझ लिया है। हर मर्ज का एक ही रामबाण इलाज। थोड़ी सी देशभक्ति का चून बंटा दो।
वर्षों से गोदान में पड़ी देशभक्ति को तोषों को भी झाड़ू-पाँछकर निकाल लिया गया है। तोप तैयार है, गोला-बारूद भर्पूर है, बस दुश्मन चाहिए।

मैंने पूछा- 'दुश्मन कौन? बताया गया- 'अपने बीच ही बहुत हैं।

पहचान कैसे होगी?

अब देशभक्ति की खपतवार हर

?आज की नई पीढ़ी डिजिटल क्रांति और उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में जी रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज का युवा तकनीकी रूप से बेहद सक्षम है, परंतु दुर्दशा यह है कि वह इस बात को भूलता जा रहा है कि यह आजादी कितनी महँगी कीमत चुकाकर मिली है।

हम अब ?बलिदानों की विस्मृति के शिकार हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खाँ और रानी लक्ष्मीबाई जैसे हज़ारों-लाखों ज्ञात और अज्ञात शहीदों ने अपना

जीवन-शैली होनी चाहिए।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक सीमाएँ



वर्तमान हमारे सुखद भविष्य के लिए न्योछावर कर दिया था। उन ?शहीदों के सपनों का भारत बनाना हम सबका परम कर्तव्य है। शहीदों ने केवल एक राजनीतिक रूप से मुक्त भारत का सपना नहीं देखा था, उनका सपना एक ऐसे भारत का था जो नैतिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से जागृत और आत्म-अभिमानी हो। यदि आज का

?वर्तमान दौर में 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का दुरुपयोग एक फैशन बन गया है। मैंने अत्यंत कड़वी लेकिन सत्य बात कही है कि अगर अस्थील गालियां देना या दूसरों का भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही किसी का अधिकार बन गया है, तो उसका यह कर्तव्य भी है कि वह समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करे। स्वतंत्रता कभी भी

पहुँचना होता है। कभी क्रांनु की गिरफ्त में आ की गए तो 'दे' कर छूट जाएँगे। हर तरफ़ सरकारी मुलाजिम हर होर और 'बैंधी' का बोलबाला। वो कहते हैं ना – 'बैंधी' वो शय कि जिससे 'लेने' प पे कड़ जाते हैं।

तो 'देने' से छूट जाते हैं और फिर मजे उड़ाते हैं।

एक पूर्व प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि विकास के लिए जो धन आर्बॉटिड होता है वह क्षेत्र के विकास में 25 टका तक भी नहीं पहुँचता। उसमें सेंध कहीं लगी? एक अंग्रेजी किताब मशहूर हुई थी 'हू मूड मंड माई चीज'। देश के विकास कार्यो में लगे 'जिम्मेदार' ही बताएँ। लेकिन वरीरअ किअड़ें देख कर हैरान है। अरे! हम 11 वीं से पाँचवीं और देखते – देखते चौथी अर्थव्यवस्था हो गए। उसे तो 'बजट के हलुए' की खुशबू तक नहीं मिली। तब इस बात का अहसास हुआ कि हम कितने 'भवतंत्र' हैं।

एक बार कलेंडर में छपाई की छोटी सी त्रुटि रह गयी। 'शिक्षा' विभाग की छुट्टियों की जगह 'भिक्षा' विभाग की छुट्टियों छप गया। गौर करने पर लगा कि बात तो कुछ हद तक सही ही है। देश और राज्यों के बजट का बहुत मामूली – सा हिस्सा अमूमन 3-5 टका ही शिक्षा विभाग को आर्बॉटिड होता है। उसमें से अधिक्तर हिस्सा कर्मचारियों के वेतन- भत्ते और पेंशन (जिसे वे हमेशा अपर्याप्त ही मानते हैं) में खर्च हो हो जाता है। सरकारी स्कूलों के भवनों की हालत विशेष रूप से गाँवों में जर्जर होती है। बरसात में उनके कमरे ढह जाते हैं और कुचल जाते हैं माता-पिता व बच्चों के भविष्य के सपने।

'उच्छृंखलता' या 'अराजकता' का लाइसेंस नहीं हो सकती। अगर संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, तो वही संविधान और हमारी नैतिक परंपराएँ हमें यह भी सिखाती हैं कि हमारी जीभ से निकले शब्द देश की अखंडता और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान न पहुँचाएँ। ?यदि हमें शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, तो प्रत्येक नागरिक को अपने स्तर पर निम्नलिखित कर्तव्यों को आत्मसात करना होगा,जैसे ?राष्ट्रीय प्रतीकों का स्वतःस्फूर्त सम्मान: तिरंगा, राष्ट्रगान, वंदे मातरम और हमारे सुरक्षा बलों का सम्मान किसी नियम या कानून के डर से नहीं, बल्कि दिल से होना चाहिए। ?नई पीढ़ी को सत्य और प्रामाणिक इतिहास का ज्ञान कराया जाए। उसे भारत के वास्तविक इतिहास, संघर्षों और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना होगा ताकि वे दुष्प्रचार का शिकार न बनें। ?सामाजिक समरसता और भ्रातृत्व भी जगाना है। जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के नाम पर देश को बाँटने वाली शक्तियों को पहचानना और सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा देना भी देशभक्ति है ।व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी, महिलाओं का सम्मान, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को प्राथमिक कर्तव्य मानना हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए।

राष्ट्र निर्माण का संकल्प
भारत अपनी स्वतंत्रता के सौवें वर्ष की ओर बढ़ रहा है। भौतिक विकास, बढ़ी-बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें और उन्नत तकनीक किसी देश का ढाँचा तो बना सकती हैं, लेकिन उसकी 'आत्मा' उसके नागरिकों के चरित्र, राष्ट्रप्रेम और नैतिक मूल्यों से ही जीवंत रहती है। यह विचार आज पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी है और मार्गदर्शन भी। यदि हमने समय रहते अपनी नई पीढ़ी को अधिकारों के साथ-साथ 'नागरिक कर्तव्यों' का पाठ नहीं पढ़ाया, तो हम अपनी स्वतंत्रता के वास्तविक

अर्थ को खो देंगे।
?आजादी एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हर भारतीय अपनी दैनिक दिनचर्या में देशभक्ति को शामिल करे। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करेगा, तभी भारत न केवल भौतिक रूप से, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी विश्वगुरु के पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो सकेगा। जिस देश में कर्तव्य की भावना प्राथमिक होगी, वहाँ अधिकारों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब हम कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जब हम कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं, जब हम रिश्तत देने और लेने से मना करते हैं, और जब हम अपने देशवासियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखते हैं, तब हम सही मायनों में देशभक्त होते हैं। एक आम नागरिक के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में देश के नियमों और व्यवस्थाओं का सम्मान करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है. सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना, ईमानदारी के साथ टैक्स चुकाना, पर्यावरण और जल का संरक्षण करना, कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचना,बच्चों को सच्चे नैतिक मूल्य और सही ज्ञान देना देशभक्ति है। एक डॉक्टर के लिए मरीज की जान बचाना और सेवा भाव रखना देशभक्ति है। किसान के लिए अन्न उपजाना और एक मजदूर के लिए ईमानदारी से निर्माण करना देशभक्ति है। एक सफाई कर्मी द्वारा अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखना उतनी ही बड़ी देशभक्ति है, जितना किसी सैनिक का सीमा पर डटे रहना। देश के नव निर्माण में यह छोटे-छोटे ब्रत – संकल्प हैं।

लोग इन सबका पालन करते रहे तो अपने देश को निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता।

बोधकथा

ये भी रहेगा नहीं

ये भी रहेगा नहीं एक बार एक राजा ने अपने राज्य के एक ज्ञानी और फकीर से कहा, ‘मुझे जीवन का कोई ऐसा सत्य बताएं जो हमेशा एक जैसा रहे और मुझे हर परिस्थिति में संगमल सके। फकीर ने एक छोटी सी अंगूठी निकाली और राजा को दी। उस पर लिखा था— ‘ये भी रहेगा नहीं’ (यह समय भी नहीं रहेगा)। फकीर ने कहा, ‘हे राजन! इस वाक्य को हमेशा याद रखना। जब आप बहुत दुखी हों, इसे	पढ़ना, दुःख कम हो जाएगा। जब आप बहुत प्रसन्न हों, तब भी इसे पढ़ना, आपका घमंड टूट जाएगा। जीवन में सुख हो या दुःख, कोई भी परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती। बुरा समय हो या अच्छा समय, वह बदलता जरूर है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। अगर आप ऐसी और भी बोध कथाएं पढ़ना चाहते हैं या किसी खास विषय (जैसे संतोष, मेहनत या बुद्ध की शिक्षा) पर कहानी चाहते हैं, तो मुझे बताएं।
--	---

इतिहास

भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन् 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से २7वतंत्रता प्राप्त की थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है।

प्रतिवर्ष इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को सम्बोधित करते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने, दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।[1] महात्मा गाँधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने काफी हद तक अहिंसक प्रतिरोध और संविनय अवज्ञा आंदोलनों में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान का उदय हुआ। विभाजन के बाद दोनों देशों में हिंसक हिंसा भड़क गए और सांप्रदायिक दंगा की अनेक घटनाएं हुईं। विभाजन के कारण मनुष्य जाति के इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ।

तो फिलहाल कैमरा खोलिए, तिरंगा उठाइए और मुस्कराइए- भारत माता की जय!

भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में लाल निशान में बंद, फार्मा और मेटल में रहा दबाव

विश्व केसरी ■
मुंबई। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 70.71 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 78,009.25 और निफ्टी 29.85 अंक या 0.12 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,366 पर था।

शेयर बाजार पर दबाव बनाने का काम फार्मा और मेटल स्टॉक्स ने किया। सूचकांकों में निफ्टी फार्मा 0.90 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.71 प्रतिशत की गिरावट के साथ लुजस थे। निफ्टी ऑटो 0.63 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.57 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 0.56 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 0.51 प्रतिशत, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.47 प्रतिशत और निफ्टी हेल्थकेयर 0.46 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं, निफ्टी मीडिया 0.96 प्रतिशत, निफ्टी कंप्यूटर इयूरेबल्स 0.76 प्रतिशत, निफ्टी इन्फ्रा 0.28 प्रतिशत, निफ्टी सर्विसेज 0.09 प्रतिशत और निफ्टी कंजशनन 0.04 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए।

सेंसेक्स पैक में भारती एयरटेल, अदाणी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, एमएंडएम, एचडीएफसी बैंक और इटरनल गेनस थे। एशियन पेट्र्स, इंडिगो, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एसबीआई, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, टाटा स्टील, ट्रेट, आईटीसी, एक्सिस बैंक और टीसीएस लूजस थे। लार्जकैप के साथ मिडकैप और



स्मॉलकैप में गिरावट देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 339.40 अंक या 0.53 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 63,782.15 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 136.55 अंक या 0.69 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 19,738.55 पर बंद हुआ।

जानकारों के मुताबिक, निवेशक एनर्जी की कीमतों और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड के आउटलुक पर ज्यादा साफ जानकारी का इंतजार कर रहे हैं और इस कारण से बाजार एक सीमित दायरे बने हुए हैं। हालांकि, मांग में सुधार के चलते कंज्यूमर इयूरेबल्स और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्टॉक्स की अगुवाई में बाजार दिन के निचले स्तरों से सुधर कर बंद हुआ। उन्होंने आगे कहा कि तिमाही के दौरान उम्मीद से बेहतर कॉर्पोरेट नतीजों और घरेलू कारकों की वजह से ‘बॉटम-अप’ स्टॉक चुनने के तरीके के लिए मौके बन रहे हैं। इसके अलावा, रुपए में स्थिरता, भारत की 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड में कमी और एफआईआई की भागीदारी में धीरे-धीरे सुधार जैसे कारक मिलकर घरेलू अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं।

शिपरॉकेट के आईपीओ ड्राफ्ट पेपर में कई कानूनी और कर विवादों का खुलासा, कंपनी पर 4 आपराधिक मामले लंबित

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स और शिपिंग प्लेटफॉर्म शिपरॉकेट ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में कंपनी और उसकी सहयोगी इकाइयों से जुड़े कई लंबित कानूनी और कर विवादों का खुलासा किया है। ये मामले संभावित निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वे कंपनी के जोखिम प्रोफाइल और भविष्य के कारोबारी प्रभावों को लेकर सवाल खड़े करते हैं।

डीआरएचपी के अनुसार, शिपरॉकेट वर्तमान में चार आपराधिक मामलों का सामना कर रही है, जिनमें कुल दावा राशि 5.39 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ दो अन्य आपराधिक कार्यवाहियां और सात कर (टेक्स) विवाद भी लंबित हैं। वहीं कंपनी की सहयोगी इकाइयों (सब्सिडियरी) के खिलाफ एक आपराधिक मामला और तीन कर संबंधी मामले चल रहे हैं, जिनमें

कुल दावा राशि 2.34 करोड़ रुपए बताई गई है।

कंपनी के आईपीओ ड्राफ्ट पेपर में एक महत्वपूर्ण मामले का भी उल्लेख किया गया है, जो वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था। इस मामले में शिपरॉकेट के सह-संस्थापक साहिल गोयल और गौतम कपूर, निदेशीय अर्जुन सेठी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी कुमार तनमय को नामजद किया गया है। इस केस में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए गए हैं। मामला फिलहाल अदालत में लंबित है और इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है।

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो

डीआरएचपी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में शिपरॉकेट का शुद्ध घाटा 79.2 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 74.4 करोड़ रुपए के घाटे से थोड़ा अधिक है। हालांकि कंपनी ने यह भी बताया कि यह स्थिति वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में काफी बेहतर है, जब उसे 595.1 करोड़ रुपए का भारी घाटा हुआ था।

राजस्व के मोर्चे पर कंपनी ने मजबूत वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2025-26 में परिचालन से प्राप्त आय 24 प्रतिशत बढ़कर 2,024.1 करोड़ रुपए हो गई। यह वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष के समान रही, जिससे कंपनी के कारोबार के विस्तार की गति बनी रहने का संकेत मिलता है।

‘चिप्स टू स्टार्टअप्स’ प्रोग्राम में 68,000 से अधिक छात्रों को मिला प्रशिक्षण, डिजाइन इकोसिस्टम भी मजबूत हुआ

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अब तक ‘चिप्स टू स्टार्टअप्स’ (सी2एस) कार्यक्रम के तहत 68,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह जानकारी सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई।

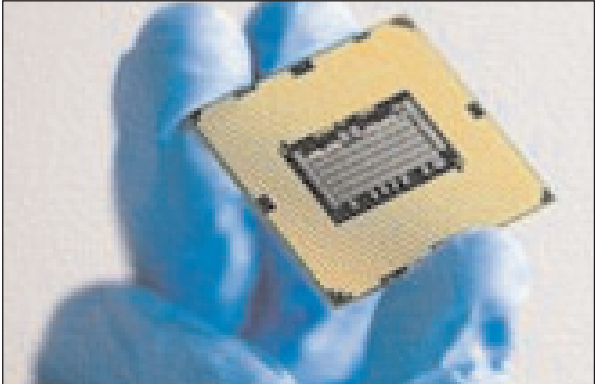
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि सी2एस कार्यक्रम का लक्ष्य सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले बोटके, एमटेक और पीएचडी स्तर के 85,000 उद्योग-तैयार पेशेवर तैयार करना है। सीटूएस कार्यक्रम के तहत देशभर के 332 शैक्षणिक संस्थानों को सिनॉप्सिस, कैडेंस, सीमेंस ईडीए, एक्सिस, कीसाइट, सिलवाका, रैसैसास-अल्टियम, एएमडी-जिलिक्स, एस्टरक्वांट, कॉम्पकार्टा, कैड्डे और एएमडी-

जिलिक्स जैसी कंपनियों के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) टूलस तक पहुंच प्रदान की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भाग लेने वाले संस्थानों ने अब तक 254 चिप डिजाइन सफलतापूर्वक ‘टेप-आउट’ किए हैं। इनमें 175 डिजाइन एससीएल, मोहाली में 180एनएम टेक्नोलॉजी नोड पर और 79 डिजाइन विदेशों में स्थित सेमीकंडक्टर फाउंड्री में तैयार किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में सी2एस कार्यक्रम के तहत 23 शैक्षणिक संस्थानों को उन्नत ईडीए टूलस तक पहुंच प्रदान की गई है, जिनका कुल उपयोग 4.34 लाख से अधिक टूल घंटे रहा है।

प्रसाद ने आगे कहा कि ये परियोजनाएं फिलहाल डिजाइन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इनके सेमीकंडक्टर फाउंड्री में टेप-आउट सहित प्रोटोटाइप वैलिडेशन की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद



है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) ने भारत के निर्यात-केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत किया है।

ईएचटीपी इकाइयों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है और वित्त वर्ष 2025-26 में इनका निर्यात 11,100 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।

ईएचटीपी योजना भारत से इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 100 प्रतिशत निर्यात-उन्मुख योजना है। एसटीपीआई, ईएचटीपी योजना के तहत सिंगल-विंडो क्लायरेंस सिस्टम के माध्यम से वैधानिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। सरकार ने बताया कि ईएचटीपी योजना के तहत कोई फंड आवंटन नहीं किया जाता है। पात्र ईएचटीपी इकाइयों को मिलने वाले प्रोत्साहन और वित्तीय लाभ ‘विदेश व्यापार नीति 2023’ के प्रावधानों के तहत निर्धारित होते हैं।

अनन्या बिरला की स्वतंत्र माइक्रोफिन के आईपीओ प्रॉस्पेक्टस में कई जोखिमों का खुलासा, असुरक्षित कर्ज और बढ़ते नकद बहिर्वाह पर चिंता

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। अनन्या बिरला और एंटीमैटर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रमोटर्ड स्वतंत्र माइक्रोफिन लिमिटेड ने सेवा यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के पास 3,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए मसौदा दस्तावेज (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस-डीआरएचपी) दाखिल किए हैं। हालांकि, कंपनी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में कई ऐसे कारोबारी, परिचालन और प्रशासनिक जोखिमों का उल्लेख किया गया है, जो संभावित निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

डीआरएचपी के अनुसार, कंपनी की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक उसकी असुरक्षित ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की कुल प्रबंधित परिसंपत्तियों (एयूएम) का 88.56 प्रतिशत हिस्सा असुरक्षित

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। अनन्या बिरला और एंटीमैटर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रमोटर्ड स्वतंत्र माइक्रोफिन लिमिटेड ने सेवा यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के पास 3,000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए मसौदा दस्तावेज (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस-डीआरएचपी) दाखिल किए हैं। हालांकि, कंपनी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों में कई ऐसे कारोबारी, परिचालन और प्रशासनिक जोखिमों का उल्लेख किया गया है, जो संभावित निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

डीआरएचपी के अनुसार, कंपनी की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक उसकी असुरक्षित ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी की कुल प्रबंधित परिसंपत्तियों (एयूएम) का 88.56 प्रतिशत हिस्सा असुरक्षित



व्यक्त की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में परिचालन गतिविधियों में उपयोग हुई शुद्ध नकदी बढ़कर 5,392.6 करोड़ रुपए हो गई, जबकि एक वर्ष पहले यह केवल 427 करोड़ रुपए थी। यानी परिचालन नकद बहिर्वाह में करीब 1,160 प्रतिशत की तेज वृद्धि हुई है। कंपनी ने बताया कि इसका मुख्य कारण तेजी से बढ़ा ऋण वितरण और लोन बढ़ा है।

कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऋण कारोबार के विस्तार के साथ नकारात्मक परिचालन नकदी प्रवाह जारी रह सकता है।

भौगोलिक एकाग्रता भी कंपनी के लिए एक जोखिम है, रूप में सामने आई है। स्वतंत्र माइक्रोफिन के कुल एयूएम का लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा केवल पांच राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में केंद्रित है।

2031 तक 11.8 लाख रोजगार और 1,380 नए जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य, राज्यों में निवेश आकर्षित करने की होड़ तेज : रिपोर्ट



विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। भारत के विभिन्न राज्य वर्ष 2031 तक करीब 11.8 लाख रोजगार अवसर सृजित करने और लगभग 1,380 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी सीबीआई साउथ एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों द्वारा बनाई गई विशेष जीसीसी नीतियां इस क्षेत्र की तेज वृद्धि का प्रमुख आधार बन रही हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 से लेकर 2026 की पहली छमाही तक जीसीसी ने भारत के शीर्ष नौ शहरों में 12.3 करोड़ वर्गफुट से अधिक कार्यालय क्षेत्र लीज पर लिया है। यह दर्शाता है कि वैश्विक कंपनियां भारत को अपने बैंक-ऑफिस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और बिजनेस ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में देख रही हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात,

राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने निवेश आकर्षित करने और जीसीसी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए विशेष नीतियां लागू की हैं। वहीं तेलंगाना, दिल्ली और तमिलनाडु ने भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं और नीति ढांचे तैयार किए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कई अन्य राज्य भी जीसीसी क्षेत्र में अवसरों और इंजीनियरिंग एवं कर रहे हैं। केरल उन राज्यों में शामिल है जिसने जीसीसी नीति का मसौदा तैयार किया है और इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत में कुल ऑफिस लीजिंग गतिविधियों में जीसीसी की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022 में यह हिस्सेदारी करीब 29 प्रतिशत थी, जो 2026 की पहली छमाही में बढ़कर लगभग 43 प्रतिशत पहुंच गई। हिस्सा नहीं रह गए हैं, बल्कि वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार में जीसीसी की भूमिका तेजी से

मजबूत हो रही है।

सेक्टरवार आंकड़ों के अनुसार, प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस (बीएफएसआई) तथा इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षेत्रों ने कुल लीजिंग गतिविधियों में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया। इनमें टेक्नोलॉजी सेक्टर की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत, बीएफएसआई की 22 प्रतिशत और इंजीनियरिंग एवं मैनुफैक्चरिंग की 16 प्रतिशत रही। सीबीआई इंडिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एवं अफ्रीका के चेयरमैन एवं सीईओ अंशुमन मैगजीन ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा जीसीसी के लिए समर्पित नीतियां इतनी तेजी से अपनाता भारत के वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव है। उन्होंने कहा कि अब जीसीसी केवल सेवा क्षेत्र का एक हिस्सा नहीं रह गए हैं, बल्कि राज्यों की आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुके हैं।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच कीमती धातुओं में दबाव, सोने-चांदी की कीमतों में 1.6 प्रतिशत तक की गिरावट

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को कीमती धातुओं में दबाव देखने को मिला। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट द्वारा ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व आर्थिक कदम उठाने की चेतावनी के बाद निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एससीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना वायदा कारोबार के दौरान अपने पिछले बंद 1,53,466 से 1,543 रुपए यानी 1 प्रतिशत गिरकर 1,51,923 रुपए प्रति 10 ग्राम के इंद्रा-डे निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी हुई और खबर लिखे जाने तक यह 0.64 प्रतिशत यानी

866 रुपए फिसलकर 1,52,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। कारोबार के दौरान सोने ने 1,53,200 रुपए का इंद्रा-डे उच्च स्तर भी छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी रही।

इसी तरह सितंबर डिलीवरी वाली चांदी वायदा में भी कमजोरी देखने को मिली।



2,33,982 रुपए का उच्च स्तर भी छुआ, लेकिन बाजार में दबाव बना रहा।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, कीमती धातुओं में यह कमजोरी उन खबरों के बाद आई है जिनमें अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ आर्थिक अलगाव और होमुंज खलाइमरूमध्य की नाकेबंदी जैसी रणनीतियों का सहारा ले सकता है। इन घटनाक्रमों ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है।

तकनीकी विश्लेषकों का कहना है कि एमसीएस सोना हाल के उच्च स्तर 1,55,500 रुपए के आसपास से दबाव में आया है और फिलहाल 1,52,500 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। उनके मुताबिक 1,53,000 से 1,53,500 रुपए का दायरा तत्काल रेंजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है।

भारत को वित्त वर्ष 27 में मजबूत एफसीएनआर रिस्पॉन्स के चलते 95 अरब डॉलर तक का पूंजी प्रवाह मिलने की संभावना: रिपोर्ट

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। मजबूत फॉरेन करेंसी नॉन-रेंजिडेंट (बैंक) एफसीएनआर (बी) इनफ्लो और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों से वित्त वर्ष 2026-27 में भारत में 90-95 अरब डॉलर का पूंजी प्रवाह आने की उम्मीद है। इससे भारत का भुगतान संतुलन (बीओपी) 64 अरब डॉलर के सरप्लस में पहुंच सकता है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, एंजेंसी ने एफसीएनआर (बी) प्रवाह का अनुमान बढ़ाकर करीब 80 अरब डॉलर कर दिया है। इसके अलावा, बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और विदेशी मुद्रा में बाहरी स्रोतों से आने वाले प्रवाह के 10-15 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है। इसके

परिणामस्वरूप, भारत के पूंजी खाते का सरप्लस अब बढ़कर करीब 108 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह महज 2 अरब डॉलर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत का बीओपी 64 अरब डॉलर के सरप्लस में रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2026 में 23.6 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2025 में 5 अरब डॉलर का घाटा रहा था।

रेंटिंग एंजेंसी ने कहा, ‘यह भारत की बाहरी स्थिति में महत्वपूर्ण मजबूती को दर्शाएगा और वैश्विक अस्थिरता के खिलाफ एक



महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करेगा।’

5 जून 2026 को घोषित अन्य नीतिगत उपायों के साथ एफसीएनआर (बी) जमा, बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) और विदेशी मुद्रा में बाहरी उधारी (ओएफसीबी) के लिए रियायती स्वैप विंडो को निवेशकों से मजबूत रिस्पॉन्स मिलता है। एंजेंसी ने बताया कि इन उपायों के जरिए 5 जून से 31 जुलाई 2026 के बीच कुल 40.8 अरब डॉलर आकर्षित हुए हैं। इनमें एफसीएनआर (बी) प्रवाह 36.7 अरब डॉलर रहा, जबकि ईसीबी और ओएफसीबी ने मिलकर 4.1 अरब डॉलर का योगदान दिया।

वर्तमान में बढ़े बैंक एफसीएनआर जमा पर 6.0-6.5 प्रतिशत की ब्याज दर दे रहे हैं, जबकि कुछ छोटे और नए बैंक करीब 7 प्रतिशत तक की दर की पेशकश कर रहे हैं।

झमयूरी कांगो : आईआईटी छोड़ 90 के दशक में बनीं नेशनल क्रश, फिल्मों को अलविदा कह बनीं कॉरपोरेट दुनिया में बड़ी शख्सियत



मुंबई । अक्सर लोग अपनी मासूम छवि व नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया में नाम और शोहरत कमाने का सपना देखते हैं, लेकिन मयूरी कांगो की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। महज 15 साल की उम्र में आईआईटी कानपुर की प्रवेश परीक्षा पास करने वाली मयूरी ने पढ़ाई छोड़कर अभिनय को चुना और 90 के दशक में अपनी मासूम छवि व शानदार अभिनय से लाखों दिलों को धड़कन बन गई। हालांकि, जब उनका करियर सफलता की ऊंचाइयों पर था, तब उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कहकर एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। उनकी यह यात्रा बताती है कि सफलता सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि जीवन में

आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी, हालांकि नियति ने उनके लिए एक अलग ही मार्ग निर्धारित किया था। जब वह अपनी मां के साथ मुंबई के एक शूट पर गई थीं तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सईद अख्तर मिर्जा की नजर उन पर पड़ी। सईद अख्तर मिर्जा ने उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस की पृष्ठभूमि पर आधारित अपनी फिल्म ‘नसीम’ (1995) में मुख्य भूमिका और कला के बीच एक रणनीतिक निर्णय लेते हुए उन्होंने फिल्म को चुना और इस प्रकार उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। ‘नसीम’ में उनके संवेदनशील और परिपक्व अभिनय ने फिल्म उद्योग के दिग्गजों का ध्यान आकर्षित किया। जाने-माने निर्देशक महेश भट्ट ने इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘पापा कहते हैं’ (1996) में जुगल हंसराज के विपरीत कास्ट किया। इस फिल्म का संगीत विशेष रूप से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। जावेद अख्तर द्वारा लिखित और उदित नारायण द्वारा गाया गया गीत ‘घर से निकलते ही’ 90 के दशक के युवाओं के लिए एक लव एथम बन गया। इस सफलता के बाद उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में काम किया। 1997 की ‘बेताबी’ फ्लॉप हुई। 1999 में ‘होगी प्यार की जीत’ सेमी-हिट रही और साल 2000 में आई फिल्म ‘बादल’ हिट रही। एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘बादल’ में मयूरी कांगो ने ‘सोनी’ नाम की एक सहायक भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में बॉबी देओल और रानी मुखर्जी नजर आए थे। लगभग 16 फिल्मों (जिनमें से आधी रिलीज भी नहीं हो सकीं) और कई टेलीविजन धारावाहिकों (जैसे ‘डॉलर बहू’ और ‘कारिश्मा: द मिरैकल ऑफ डेस्टिनी’) में काम करने के बाद मयूरी कांगो ने 28 दिसंबर, 2003 को एनआरआई व्यवसायी आदित्य हिल्लों से शादी की और संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। अमेरिका में उन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू यॉर्क से मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए की डिग्री हासिल की और 2007 में स्नातक की। यह कदम उनके पेशेवर पुनर्जागरण की नींव साबित हुआ। अपनी व्यावसायिक कुशाग्रता से उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और विज्ञापन के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। 2007 में 360आई न्यूयॉर्क में एसोसिएट मीडिया मैनेजर के रूप में करियर शुरू किया। 2012 में ‘जेनिश’ भारत के चीफ डिजिटल ऑफिसर बनीं। 2016 में ‘पर्फॉर्मिक्स’ के मैनेजिंग डायरेक्टर और 2019 में गूगल इंडिया में ‘इंक्स्ट्री हेड- एजेंसी पार्टनरशिप बनीं’। मौजूदा समय में वह सीईओ की भूमिका में भारत के ऑपरेशन्स के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर मीडिया, टेक और एआई समाधानों को आकार दे रही हैं।

करिश्मा कपूर ने बताया ‘महबूब मेरे’ का मजेदार किस्सा, कहा- गाने में मैं ऋतिक रोशन को ढूंढ रही थीं

विश्व केसरी ■ **मुंबई**। अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने 90 के दशक से हिंदी सिनेमा में राज किया है और अभी भी उनके प्रति दीवानगी लोगों के दिलों में कायम है। अभिनेत्री ने हाल ही में फिल्म ‘फिजा’ के मशहूर गाने ‘महबूब मेरे’ की अनकही कहानी बताई। अभिनेत्री ने बताया कि फिल्म में उन्हें गाने की सिचुएशन काफी अजीब लगी थी, जब सुष्मिता सेन गाने पर डांस कर रही थीं, जबकि वह खुद फिटम में ऋतिक रोशन को ढूंढ रही थीं। अभिनेत्री ने इस बात का खुलासा डांस रियलिटी शो ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5’ में किया था। शो के स्पेशल एपिसोड में कंटेस्टेंट वैदेही और रोमशा ने ‘महबूब मेरे’ समेत कुछ टाइमलेस बॉलीवुड गानों पर दमदार परफॉर्मेंस दी थी। परफॉर्मेंस के बाद करिश्मा ने इस गाने से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया और फिल्म ‘फिजा’ से जुड़ा एक कम जाना-पहचाना किस्सा भी बताया।



करिश्मा ने कहा, ‘आप लोगों इस गाने में भी हूं। ये सिचुएशन बहुत को शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन अलग थी और मुझे भी बहुत अजीब

लग रहा था कि सुष्मिता डांस कर रही थीं और मैं गाने के बीच में ऋतिक को ढूंढ रही थी। ये फिल्म ‘फिजा’ का गाना है। तो हां, मेरे लिए ये एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन थी। सॉन्ग ‘महबूब मेरे’ वर्ष 2000 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म ‘फिजा’ का एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार गाना है। इस गाने में अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने एक स्पेशल अपीयरेंस (कैमियो) में शानदार डांस किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। सुष्मिता सेन वाला यह गाना उस समय के यादगार डांस नंबरों में से एक बन गया, जबकि ‘फिजा’ में ऋतिक रोशन, करिश्मा कपूर और डिंपल कपाड़िया ने अहम रोल निभाए थे। फिजा एक बेहतरीन हिंदी ड्रामा और क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे खालिद मोहम्मद ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में करिश्मा कपूर, ऋतिक रोशन और जया बच्चन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।

शेखर कपूर ने शेयर की श्रीदेवी के साथ पुरानी तस्वीर, बोले- ‘कैमरे के सामने आते ही जैसे जादू हो जाता था’

विश्व केसरी ■ **मुंबई**। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा कई तरह के किरदार निभाए। फिर चाहे ‘सदमा’ की मानसिक रूप से कमजोर लड़की वाला रोल हो या फिर ‘इंग्लिश विलिंग’ की आत्मविश्वासी गुंथिणी वाली भूमिका की बात हो, उन्होंने अपने अभिनय से अपना एक अलग स्टारडम तैयार किया। आज भी लोग उन्हें दिल से याद करते हैं। इस कड़ी में निर्देशक शेखर कपूर ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर श्रीदेवी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और ‘मिस्टर इंडिया’ के दिनों के बारे में बात करते हुए बताया कि कैमरे के सामने श्रीदेवी को देखना उनके लिए किसी जादुई अनुभव से कम नहीं था। शेखर कपूर ने इंस्टाग्राम पर

श्रीदेवी के साथ अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की। उन्होंने इसे श्रीदेवी के साथ अपनी सबसे शुरुआती तस्वीर बताया। तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘श्रीदेवी का चेहरा कभी नहीं बदला। उनकी आंखों में वही चमक दिखाई दे रही है, जो बाद में ‘मिस्टर इंडिया’ में नजर आई थी। दुनिया श्रीदेवी को एक बड़ी स्टार के रूप में याद करती है, लेकिन मैं उन्हें एक अलग तरह से याद करता हूं। मेरे लिए श्रीदेवी सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि ‘डायरेक्टर की सबसे अच्छी दोस्त’ थीं।’ शेखर कपूर ने ‘मिस्टर इंडिया’ के दौरान श्रीदेवी के साथ अपनी बॉन्डिंग को भी याद किया। उन्होंने कहा, ‘श्रीदेवी के साथ शानदार साझेदारी के बिना ‘मिस्टर इंडिया’ जैसी

फिल्म बन ही नहीं सकती थी। जब मैं श्रीदेवी के साथ फिल्म पर काम कर रहा था, तब मुझे हर दिन सेट पर जाने की उत्सुकता रहती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं होता था कि उस दिन श्रीदेवी अपने अभिनय से क्या नया दिखाने वाली हैं। वह हर बार किसी न किसी तरह से चौंका देती थीं।’ निर्देशक ने श्रीदेवी के कैमरे के सामने और कैमरे से दूर रहने के अंदाज का फर्क भी बताया। उन्होंने कहा, ‘जब कैमरा श्रीदेवी पर नहीं होता था तो वह बहुत शांत होकर अपनी कुर्सी पर बैठी रहती थीं। वह अपनी स्टारडम को लेकर किसी तरह का दिखावा नहीं करती थीं। वह सेट पर ही सामान्य तरीके से बैठी रहती थीं। लेकिन जैसे ही कैमरा उनकी तरफ घूमता था, सब कुछ बदल जाता था।’

पृथ्वीराज की ‘खलीफा’ को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, 20 अगस्त को रिलीज होगी थ्रिलर फिल्म

विश्व केसरी ■ **मुंबई**। पृथ्वीराज सुकुमारन की अपकमिंग फिल्म ‘खलीफा’ को लेकर दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निर्देशक वैसाख की रिवेंज थ्रिलर को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है और अब फिल्म की रिलीज का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट दे दिया है। फिल्म में पृथ्वीराज मुख्य भूमिका में हैं और वह आमिर अली नाम के किरदार में नजर आएंगे। अभिनेता ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की जानकारी साझा की। पृथ्वीराज ने इंस्टाग्राम पर यह अपडेट शेयर करते हुए लिखा, ‘फिल्म ‘खलीफा’ को सेंसर से यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब यह फिल्म 20 अगस्त 2026 से दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।’ फिल्म को लेकर मेकर्स पहले ही कई किरदारों की जानकारी सामने ला चुके हैं। अभिनेत्री मोहिनी फिल्म में नूरजहां का किरदार निभा रही हैं, जबकि कायरा वासुदेवन के किरदार का नाम वैष्णवी है। वहीं अभिनेता शम्मी थिलकान राघवन के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म में इन किरदारों की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर मेकर्स ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है। बता दें कि ‘खलीफा’ की शूटिंग इसी साल जून में पूरी हो गई थी। फिल्म के कुछ सीन्स दुबई में शूट किए गए। इसके लिए फिल्म की टीम इस साल की शुरुआत में दुबई पहुंची थी। फिल्म का टीजर रिलीज किया जा रहा है, जिसमें कहानी एक न्यूज बुलेटिन से शुरू होती दिखाई गई थी। इसमें बताया गया कि पुलिस और कस्टम अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट से चल रहे करोड़ों डॉलर के सोने की



तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पता लगाया है। इस नेटवर्क का संबंध लंदन, नेपाल और केरल से है। इसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति से कस्टम अधिकारी पनिकर पूछताछ करता है। पनिकर उसे आमिर के बारे में बताते हुए उड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि आमिर अब खत्म हो चुका है और भारत में कदम रखते ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी दौरान वह कोफेपोसा कानून का भी जिक्र करता है। लेकिन पूछताछ के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ही पनिकर से सवाल कर बैठता है कि क्या उसे पता है कि कोफेपोसा

कानून की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके बाद वह पुराने समय के कुछ बड़े नामों का जिक्र करता है और बताता है कि उत्तर भारत में सुकुर नरेन बखिया और हाजी मस्तान, जबकि दक्षिण भारत में मुदलियार और मम्बारायक्कल अहमद अली जैसे नाम चर्चा में थे। वह आगे बताता है कि आमिर अली उसी अहमद अली का पोता है। इसके बाद वह अधिकारी को आमिर को पकड़ने की चुनौती देता है और कहता है कि अगर वह आमिर को पकड़ लेता है, तभी उसे असली ‘फायरवर्क्स’ देखने को मिलेंगे।

भारत और जर्मनी की वायु सेनाओं के बीच पहली एयर स्टाफ वार्ता, रक्षा सहयोग को नई गति

विश्व केसरी ■
नई दिल्ली। भारत और जर्मनी की वायु सेनाओं के बीच पहली एयर स्टाफ वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह वार्ता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

भारतीय वायुसेना के अनुसार, पहली बार आयोजित इस वार्ता ने दोनों पक्षों को आपसी सैन्य सहयोग को और गहरा करने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाएं तलाशने के लिए महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराया। वार्ता के दौरान सैन्य प्रशिक्षण, ऑपरेशनल स्तर पर आपसी आदान-प्रदान और सैन्य क्षमताओं के विकास से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया। दोनों वायु सेनाओं के बीच नियमित संवाद और पेशेवर अनुभवों के आदान-प्रदान से आपसी समझ तथा



परिचालन सहयोग को और मजबूत करने की संभावनाएं बनी हैं।

गौरतलब है कि भारत और जर्मनी के बीच वायु क्षेत्र में सैन्य सहयोग पहले भी विभिन्न अभ्यासों और पेशेवर आदान-प्रदान के माध्यम से आगे बढ़ा है। वर्ष 2024 में जर्मन वायुसेना ने भारत में आयोजित तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय वायु

भारतीय वायुसेना के मुताबिक 11 अगस्त से शुरू हुई यह चार दिवसीय पहली एयर स्टाफ वार्ता भारत-जर्मनी रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आने वाले समय में प्रशिक्षण, परिचालन आदान-प्रदान और क्षमता विकास के क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशे जाने की उम्मीद है। वहीं भारत-इंडोनेशिया के बीच आर्मी टू-आर्मी स्टाफ वार्ता भी हुई है। भारत व इंडोनेशिया के बीच इस सैन्य वार्ता का उद्देश्य रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। यहां रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने और मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने पर दोनों देशों ने सहमति दी है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग व संयुक्त प्रशिक्षण का दायरे बढ़ाने पर दोनों पक्ष राजी हुए हैं।

11 से प्रारंभ हुई दोनों देशों की यह सैन्य वार्ता 13 अगस्त तक जारी रही। वार्ता में दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने और आपसी संबंधों को और गहरा करने पर विस्तार से चर्चा हुई।

ग्लोबल स्पेस मार्केट का 10 फीसदी हिस्सा हासिल कर सकता है भारत : अमेरिकी वाणिज्य विभाग

विश्व केसरी ■

वॉशिंगटन। अगले सात सालों में ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी पांच गुना बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पॉलिसी में सुधार और अमेरिका के साथ करीबी रिश्तों से भारत के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की वृद्धि में तेजी आएगी। यह जानकारी अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने दी है।

अभी ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम है। लेकिन विभाग के इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आमत से 'एयरोस्पेस एंड डिफेंस एक्सपोर्टर अलर्ट' में अनुमान लगाया है कि अगले पांच से सात सालों में यह हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। विभाग ने कहा, 'भारत का प्राइवेट सेक्टर स्पेस इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और भारत सरकार के निजीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों से इंटरनेशनल स्पेस कंपनियों के लिए भी मौके बनेंगे'।



इस अलर्ट में भारत के स्पेस सेक्टर को 'मार्केट ऑफ द मंथ' बताया गया है। इसमें अमेरिकी कंपनियों के लिए सैटेलाइट सिस्टम, एडवांस्ड स्पेसफ्लाइट, कनेक्टिविटी, मैनुफैक्चरिंग और संबंधित टेक्नोलॉजी में निवेश के मौकों पर जोर दिया गया।

1963 में भारत के पहले रॉकेट लॉन्च के समय से ही अमेरिका और भारत स्पेस के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। वह रॉकेट अमेरिका में बना 'नाइक-अपबचे' था। तब से यह

साझेदारी वैज्ञानिक आदान-प्रदान, संयुक्त वर्किंग ग्रुप और मिलकर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के जरिए बढ़ी है। नासा और अमेरिकी कंपनियों ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) को टेक्नोलॉजी और पार्ट्स भी सप्लाई किए हैं।

विभाग ने कहा कि भारत के नए स्पेस स्टार्टअप्स अमेरिका में अपने कामकाज और मैनुफैक्चरिंग की मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

संक्षिप्त खबर

एच-1बी वीजा फीस से अमेरिका की नौकरियां जा सकती हैं विदेश : लॉमेकर राजा कृष्णमूर्ति

विश्व केसरी ■
वॉशिंगटन। भारतीय-अमेरिकी लॉमेकर राजा कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि नए एच-1बी वीजा पर 100,000 डॉलर की फीस से अमेरिकी कंपनियों को अपना काम विदेश ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे देश की कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा।

कृष्णमूर्ति ने 'स्पिल द टी' इंटरव्यू सीरीज के एक एपिसोड में कहा, 'आप या तो टैलेंट को देश में ला सकते हैं या काम को विदेश भेज सकते हैं।' इलिनोइस के डेमोक्रेट लॉमेकर ने कहा, 'ये कंपनियां बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगी और काम नहीं रोकेगी। कृष्णमूर्ति ने कानूनी आप्रवासन (इमिग्रेशन) में आने वाली बाधाओं में शामिल 100,000 डॉलर की फीस पर चर्चा के दौरान यह बात कही। इंटरव्यू लेने वाले ने बताया कि वित्त वर्ष 2024 में सभी एच-1बी वीजा में से 71 प्रतिशत भारतीय नागरिकों को मिले थे और पूछा कि इस पॉलिसी का भारतीय-अमेरिकियों और अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता पर क्या असर पड़ेगा।

कृष्णमूर्ति ने कहा, 'मेरा मतलब है, इसका बुरा असर दोनों पर पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रतिस्पर्धी माहौल दुनिया के सबसे बेहतरीन टैलेंट को आकर्षित करने पर निर्भर करती है, चाहे वे भारत, चीन या स्वीडन के लोग हों।



जापान में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत

विश्व केसरी ■
टोक्यो। पूर्वी जापान में गुरुवार से शुक्रवार सुबह तक हुई भारी बारिश के कारण कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई इलाकों में बाढ़ आ गई। खराब होते मौसम के बीच अधिकारियों के अलर्ट पर रहने के दौरान जापान की मौसम एजेंसी ने टोक्यो के पास चिबा प्रांत की एक-तिहाई से अधिक नगरपालिकाओं के लिए भारी बारिश की सबसे ऊंची 'लेवल 5' की चेतावनी जारी की।

जापान की क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने बताया कि इचिकावा में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, साकुरा में पानी से भरी सड़क पर एक कार में फंसी 66 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि चिबा प्रीफेक्चर में पानी से भरी सड़क पर एक व्यक्ति बेसुध हालत में मिला और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई। साथ ही, साकुरा में गिरे हुए मिले एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। चिबा प्रीफेक्चरल पुलिस ने बाद में दो लोगों की मौत की पुष्टि की। रिपोर्ट के मुताबिक, चिबा और टोक्यो के कई हिस्सों में बारिश की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बाधित हुआ, जिससे यात्री सड़कों पर फंस गए। प्रीफेक्चर में एक सरकारी इमारत को फंसे हुए यात्रियों के लिए खोला गया था, जहां लगभग 1,800 लोग जमा हुए। चिबा, इचिकावा और दूसरी नगरपालिकाओं के अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा उपाय करने को कहा, क्योंकि पूरे इलाके में बाढ़ आ गई थी।



ऑस्ट्रेलिया: सिडनी एयरपोर्ट पर तीसरे रनवे से जुड़ी घटना की जांच कर रहे अधिकारी

विश्व केसरी ■
सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन सुरक्षा जांचकर्ता के प्रमुख ने शुक्रवार को अहम बयान दिया। बयान में कहा गया कि मौजूदा समय में एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर सिडनी एयरपोर्ट पर दो प्लेन से संबंधित सुरक्षात्मक हादसों के बारे में रिपोर्ट करने में देरी क्यों की गई।

ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने गुरुवार रात बताया कि उसने 9 अगस्त को हुई रनवे पर घुसपैठ की एक घटना की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में मध्य ऑस्ट्रेलिया के आयर्स रॉक एयरपोर्ट जाने वाली क्वांटस की



फ्लाइट क्यू एफ 728 और पर्थ जाने वाली वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट वीए 555 शामिल थीं।

एटीएसबी के बयान में कहा गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि उन्हें गुरुवार तक इस सुबह लगभग 10 बजे सिडनी से वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट को

रिपब्लिकन जांच में आरोप: हार्वर्ड ने अमेरिकी सुरक्षा से अधिक चीन के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी

विश्व केसरी ■

वॉशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में हुई कांग्रेस की जांच में आरोप लगाया गया है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के बजाय चीन के साथ फायदेमंद रिश्तों को प्राथमिकता दी और बीजिंग की सेना तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी संस्थाओं के साथ रिसर्च के संबंध बनाए रखे।



कांप्रोमाइज्ड इंडिपेंडेंस: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीसीपी का प्रभाव' नामक 53 पन्नों की रिपोर्ट हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन चाइना और हाउस एजुकेशन एंड वर्कफोर्स कमेटी ने जारी की। कमेटी ने बताया कि उन्होंने हार्वर्ड और चीनी सरकार के हजारों पेजों के दस्तावेजों की समीक्षा की, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से बातचीत की और कई गवाहों के बयान सुने। सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन जॉन मूलरान ने कहा, 'अमेरिकी लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज अमेरिकी रिसर्च और इन्वोवेशन की रक्षा करेंगी और इंडस्ट्रियल बेस से जुड़ी यूनिवर्सिटीज कभी भी हमारे देश के दुश्मनों के हितों को

आगे नहीं बढ़ाएंगी। अभी, हार्वर्ड इस उम्मीद पर खरा उतरने में नाकाम हो रहा है।' उन्होंने कहा, 'चीन-विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा होने देने से लेकर पीएलए से जुड़ी संस्थाओं के साथ गलतियां की हैं और अब उसे और गलतियों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि हार्वर्ड देश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज अमेरिकी रिसर्च और इंडस्ट्रियल बेस से जुड़ी यूनिवर्सिटीज के स्कॉलर्स के साथ मिलकर काम किया।

इसमें कहा गया है कि कुछ रिसर्च ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी थीं जिनका इस्तेमाल आम लोगों से जुड़ी थीं जिनका इस्तेमाल आम लोगों से जुड़ी था, जो अमेरिकी के लिए हो सकता है, जैसे कि रोबोटिक्स।

इसमें यह भी कहा गया है कि हार्वर्ड के 'चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ' ने एक एजुकैटिव एजुकेशन प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसमें शायद 'शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पस' के सदस्य शामिल हुए हों। इस चीनी पैरामिलिट्री संगठन पर अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने प्रतिबंध लगाया हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र ने दी चेतावनी, अल-कायदा बांग्लादेश में आतंकवादी सेल बनाने की कोशिश कर रहा

विश्व केसरी ■

ढाका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चेतावनी दी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा (एक्यूआईएस) बांग्लादेश को आधार बनाकर आतंकवादी सेल स्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

यह निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र की विश्लेषणात्मक सहायता एवं प्रतिबंध निगरानी टीम की 38वीं रिपोर्ट में सामने आया है। यह रिपोर्ट इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा और उससे जुड़े संगठनों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति को सौंपी गई है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले पर हुआ हमला एक्यूआईएस से जुड़ा था। साथ ही, संगठन द्वारा बांग्लादेश को आतंकवादी नेटवर्क खड़ा करने के आधार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिशों पर चिंता जताई गई है। इस पृष्ठभूमि में निगरानी टीम ने चेतावनी दी है कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद का खतरा और अधिक बढ़ गया है।



लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को उस जनविद्रोह के बाद देश छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा था, जिसमें इस्लामवादी तत्वों की प्रमुख भूमिका बताई गई थी। इसके बाद से यह आशंका बढ़ गई है कि आतंकवादी संगठनों को

वहां अपनी गतिविधियां फैलाने के लिए अनुकूल जमीन मिल सकती है। एक्यूआईएस की स्थापना वर्ष 2014 में अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी ने की थी। रिपोर्ट में कहा गया है, एक्यूआईएस एक बिखरे हुए समूह से विकसित होकर एक क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन का रूप लेता जा रहा है।' इसमें आगे कहा गया कि संगठन ने लॉजिस्टिक्स और वित्तीय नेटवर्क स्थापित कर लिए हैं तथा अब वह बड़े संगठित ढांचों के बजाय छोटे, विकेंद्रीकृत और बिखरे हुए सेल के माध्यम से काम कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के आकलन में इस घटनाक्रम को दक्षिण एशिया के सुरक्षा माहौल में व्यापक गिरावट से जोड़ा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक आतंकवादी खतरे का स्तर कुल मिलाकर लगभग समान बना हुआ है।

कोलंबिया भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 273 हुई, 3,824 घायल और 377 लोग लापता

विश्व केसरी ■

बोगोटा। कोलंबिया में सोमवार को आए भूकंप से तबाही मची हुई है। नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर रिस्को मैनेजमेंट के डायरेक्टर डेविड तामायो ने बताया कि सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 273 हो गई है। तामायो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हमारे पास 40,753 प्रभावित परिवारों, 97,515 प्रभावित लोगों और 273 मौतों की रिपोर्ट है। उन 273 मौतों में से 250 रक्त चिकित्सा विभाग में आ चुके हैं, 227 की पहचान की जा चुकी है और 189 को उनके परिवारों की सौंप दिया गया है।'



उन्होंने यह भी कहा कि भूकंप में 3,824 लोग घायल हुए और 377 लोग लापता हो गए। बुनियादी ढांचे के संदर्भ में, तामायो ने कहा कि 12,584 घर नष्ट हो गए और 74,873 क्षतिग्रस्त हो गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि भूकंप के कारण 172 इमारतें ढह गईं और 2,198 स्कूल और शैक्षणिक संस्थान, 825 सामुदायिक केंद्र, 216 स्वास्थ्य केंद्र और पांच हवाई अड्डे प्रभावित हुए।

कोलंबिया भूकंप से हुए नुकसान की निगरानी के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और हाई-रिजॉल्यूशन इमेज का उपयोग किया जा रहा है। जमीन पर, खोज और बचाव दल मलबे के नीचे लापता लोगों का पता लगाने के लिए डॉग स्कवायड के साथ काम करते रहे।

कोलंबियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने कहा कि चोको के उत्तर-पश्चिमी विभाग में सैन जोस डेल पालमार में गुरुवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 9:42 बजे 4.2 तीव्रता का एक नया झटका दर्ज किया गया, जो सोमवार के भूकंप का केंद्र था।

इस बीच, मानविय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसीएचए) और उसके सहयोगी कोलंबिया में विनाशकारी भूकंप के लिए सरकार के नेतृत्व वाली प्रतिक्रिया का समर्थन किया।

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय यूएई के दो टैंकरों पर हमला, विदेश मंत्रालय ने की ईरान की निंदा

विश्व केसरी ■
अबू धाबी। स्थानीय अधिकारियों और मीडिया ने शुक्रवार सुबह बताया कि गुरुवार शाम को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के दो जहाजों पर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय हमला किया गया।

सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में, यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरान के हमलों की निंदा की और ईरान से इन हमलों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का खुला उल्लंघन है, जिसमें नेविगेशन की आजादी के महत्व की पुष्टि की

विश्व केसरी ■
दबाव या ब्लैकमेल के हथियार के तौर पर बनाने या अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों में बाधा डालने को अस्वीकार किया गया था।

मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना और होर्मुज जलडमरूमध्य का इस्तेमाल आर्थिक



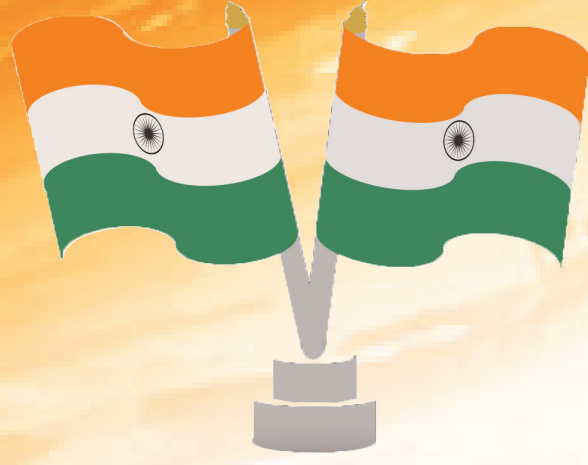
दबाव या ब्लैकमेल के हथियार के तौर पर बनाने, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस द्वारा समुद्री डकैती जैसा काम है। साथ ही, यह क्षेत्र की स्थिरता, वहां के लोगों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। मंत्रालय ने आगे कहा, 'यूएई ने इस

बात पर भी जोर दिया कि ईरान को इन बिना उकसावे के किए गए हमलों को रोकना चाहिए, सभी तरह की शत्रुता को तुरंत खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होना चाहिए और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह और बिना किसी शर्त के फिर से खोलना चाहिए।

सरकारी समाचार एजेंसी 'एम्परेट्स न्यूज एजेंसी' के हवाले से सिन्हुआ ने बताया कि कंपनी ने पुष्टि की है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। एक बयान में, एडीएनओसी ने नाविकों की सुरक्षा और भलाई की रक्षा करने के साथ-साथ नेविगेशन की आजादी और समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।



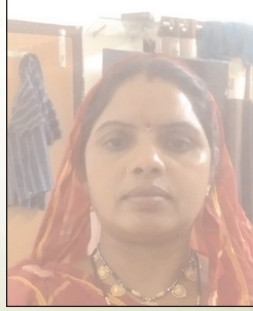
मान. श्रीमती कुसुम पैकरा
अध्यक्ष जनपद पंचायत कसडोल



**स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक
बधाई एवं शुभकामनाएं...**



मान. श्री देवानंद नायक
उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कसडोल



**विनीत: मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कसडोल जिला
बालौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)**



मान. श्री नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री



मान. श्री अमित शाह जी
केन्द्रीय गृहमंत्री



मान. श्री विष्णु देव साय जी
मुख्यमंत्री (छ.ग.)



मान. श्री टंकुराम वर्मा जी
कैबिनेट मंत्री (छ.ग.)



मान. श्री अरुण साव जी
उप मुख्यमंत्री (छ.ग.)



मान. श्री विजय शर्मा जी
उप मुख्यमंत्री (छ.ग.)



गौरीशंकर अग्रवाल
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छ.ग शासन

**स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई
एवं शुभकामनाएं...**



संकलनकर्ता :- प्रवीण ढोमने कसडोल



दशरथ पैकरा (सभापति)
लोकनिर्माण विभाग
नगर पंचायत कसडोल

adani



आज़ादी के 79 साल

संघर्ष से सम्मान तक,
सपनों से नए भारत तकयह उत्सव उस भारत का है
जो हर चुनौती के बाद और मज़बूत होकर उभरता है,
और हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है।अदाणी परिवार की ओर से
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

GSTIN:-22ACPPN4332B1ZO

स्वतंत्रता दिवस
की
15th AUGUST
हार्दिक शुभकामनाएं!
— जय हिन्द —

वंदे मातरम् | जय हिन्द | भारत माता की जय

आइए, हम सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए समर्पित हों और भारत को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान दें।

शिवशंकर सोनपिपरे
IFWJ, राष्ट्रीय सचिव

अमित मिश्रा
IFWJ, राष्ट्रीय काउंसलर

डॉ. निर्मला शर्मा
प्रदेश अध्यक्ष
न्यू छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट फाउंडेशन

हनीफ मेमन
बिलासपुर जिला अध्यक्ष

न्यू छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट फाउंडेशन
सत्य • निष्पक्षता • साहस
PRESS
NCJF
NEW CHHATTISGARH JOURNALIST FOUNDATION
• पत्रकारिता की शक्ति, समाज की उन्नति •

एकता में है शक्ति,
स्वतंत्रता में है गर्व,
आओ मिलकर करें
भारत का नवनिर्माण!

स्वतंत्रता की शान,
हमारी पहचान
गर्व से कहो हम
भारतीय हैं महान!

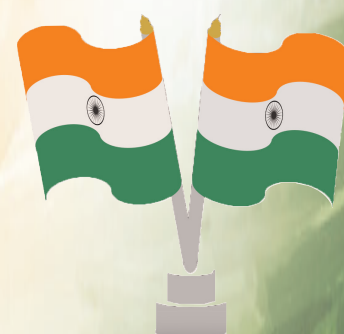
समस्त देशवासियों को

15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक
शुभकामनाएं!

खाद्य विभाग कसडोल

शिवाजी पब्लिक स्कूल -पुरानी
बस्ती रायपुर छ.ग. प्रदेश व देश
वासियों को स्वतंत्रता दिवस की
शुभकामनाएं बधाईयां

मुकेश शाह

प्रदेश एवं देशवासियों को
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक
शुभकामनाएं एवं बधाईयां

विनीत: एक शुभचिंतक

adani



आज़ादी के 79 साल

संघर्ष से सम्मान तक,
सपनों से नए भारत तक

यह उत्सव उस भारत का है
जो हर चुनौती के बाद और गज़बूत होकर उभरता है,
और हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है।

अदाणी परिवार की ओर से
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

DOC- 20260813-wA0014